

6 girls rescued from orchestra troupes; 5 held

Sandeep Bhaskar

htpatna@hindustantimes.com

BETTIAH: Sanichari police in Bihar's West Champaran district rescued six girls — five of them hailing from West Bengal and one from neighbouring Nepal — from two orchestra troupes on Sunday, police said.

They also arrested five per-

**NHRC DIRECTED
THE BETTIAH SP
TO TAKE ACTION
FOLLOWING A
COMPLAINT BY
AN NGO**

sons on charges of alleged human trafficking, the police added.

Rajnish Priyadarshi, sub divisional police officer (SDPO), Sadar -2 said that acting on a tip off, a police team raided two orchestra troupes at Bahuharwa village and rescued six girls during the operation.

"One of the girls from West Bengal alleged that she was pregnant. Probe is on," he added.

The National Human Rights Commission (NHRC) has directed Bettiah superintendent of police Shaurya Suman to take action following a complaint from an NGO alleging that several girls had been trafficked from various states to West Champaran.

Police were yet to register a case at the time of filing this report.

बंगालियों की प्रताड़ना का पिछला हिसाब और अगली राजनीति

पश्चिम

बंगाल के मुख्यमंत्री और भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के नेता शुभेंदु अधिकारी ने प्रदेश की सत्ता संभालते ही कई ऐतिहासिक और सख्त प्रशासनिक घोषणाएं की हैं। यह राज्य के प्रशासनिक ढांचे को नया रूप देने की एक बड़ी कवायद है। शुभेंदु अधिकारी ने शनिवार को शीर्ष प्रशासनिक और पुलिस अधिकारियों के साथ अपनी पहली समीक्षा बैठक में निर्देश दिया कि राज्य के सभी थानों को पिछले 5 वर्षों के दौरान हुई पुलिस ज्यादती और उत्पीड़न की शिकायतों को अनिवार्य रूप से स्वीकार करना होगा। यानी वे सभी मामले जो 2021 से अब तक हैं और अभी तक पुलिस ने उन्हें दर्ज नहीं किया है। अब ऐसे लोग या भाजपा कार्यकर्ता, जिनके पास उत्पीड़न की पुरानी शिकायतें हैं, वे अब थाने जाकर दर्ज कर सकते हैं।

ऐसी शिकायतों का मुख्य संबंध राजनीतिक हिंसा, अवैध वसूली, कट मनी और तोला बाजी और चुनावी गड़बड़ियों से रहा है। हजारों मामले ऐसे बताए जाते हैं, जिनमें पीड़ितों ने डर या पुलिस की निष्क्रियता के कारण औपचारिक शिकायत दर्ज नहीं करवाई या पुलिस ने उन्हें दर्ज करने से मना कर दिया। विपक्षी कार्यकर्ताओं (विशेषकर भाजपा) द्वारा अपने घरों से बेदखल किए जाने और संपत्ति में तोड़फोड़ की कई शिकायतें राजनीतिक और सामाजिक दबाव के कारण थानों तक नहीं पहुंच पाईं। चुनाव बाद की हिंसा के दौरान महिलाओं के उत्पीड़न और छेड़छाड़ के हजारों मामले सामने आए, जिनमें से कई सामाजिक कलंक और धर्मकियों के डर से पुलिस में औपचारिक रूप से दर्ज नहीं हो सके। 2021 के विधानसभा चुनावों के बाद बड़े पैमाने पर

हुई हिंसा के कारण राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की एक जांच समिति बनी थी। समिति ने पाया था कि बहुत सी शिकायतें थानों में नहीं ली गईं और राज्य में कानून-व्यवस्था की स्थिति खराब थी।

शुभेंदु अधिकारी ने 4 प्रमुख श्रेणियों का उल्लेख किया, जिनके तहत पीड़ित लोग अब थानों में अपनी नई शिकायतें या प्राथमिकी दर्ज कर सकते हैं, जिनमें राजनीतिक हिंसा, पुलिस बर्बरता, महिला उत्पीड़न, जबरन वसूली और रिश्वतखोरी शामिल हैं। शुभेंदु अधिकारी की बैठक राजनीतिक रूप से भी बेहद प्रतीकात्मक रही, क्योंकि इसका आयोजन डायमंड हार्बर में किया गया था, जो पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के भतीजे और टी.एम.सी.



अकु श्रीवास्तव

महासचिव अभिषेक बनर्जी का लोकसभा क्षेत्र है। यानी सबसे ज्यादा मामले यहीं के हो सकते हैं और शिकायतें तो बहुत ही होंगी। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी की अभिषेक बनर्जी के खिलाफ रणनीति आक्रामक और कानूनी कार्रवाई पर केंद्रित है।

चुनाव प्रचार के दौरान कथित तौर पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ भड़काऊ बयान देने के आरोप में अभिषेक बनर्जी के खिलाफ एफ.आई.आर. दर्ज करवाई गई है। शुभेंदु अधिकारी ने अभिषेक बनर्जी के स्वामित्व वाली कंपनी 'लीप्स एंड बाउंड्स' की 24 संपत्तियों की सूची का खुलासा किया है और उनकी जांच की बात कही है।

इसके अलावा मुख्यमंत्री ने एक और बड़ा

प्रशासनिक कदम उठाते हुए ममता बनर्जी सरकार के कार्यकाल में गठित पुलिस वैल्फेयर बोर्ड को तत्काल प्रभाव से भंग करने का ऐलान किया। शुभेंदु अधिकारी ने आरोप लगाया कि यह बोर्ड अपने मूल उद्देश्यों से भटक गया था और एक राजनीतिक संगठन की तरह काम कर रहा था।

मुख्यमंत्री बनने के बाद अपनी पहली कैबिनेट बैठक में, उन्होंने पश्चिम बंगाल में आयुष्मान भारत योजना और जनगणना कार्य को तुरंत लागू करने की मंजूरी दी। साथ ही, केंद्र की सहायता वाली अन्य योजनाओं को भी राज्य में हरी झंडी दे दी गई है। राज्य में अवैध वसूली सिंडिकेट और टोल नाकों को बंद करने के निर्देश दिए गए हैं। ऑटो चालकों, ई-रिक्शा चालकों या फेरीवालों से कोई भी अवैध वसूली नहीं करने के निर्देश भी दिए गए हैं। ऐसा होने पर लोग सीधे पुलिस स्टेशन जाकर शिकायत दर्ज कर सकते हैं।

प. बंगाल में सबसे बड़ी समस्या सरकारी योजनाओं का लाभ देने, आवास आबंटन या सरकारी नौकरियों के नाम पर तृणमूल कार्यकर्ताओं और स्थानीय नेताओं द्वारा अवैध रूप से 'कटमनी' वसूली की रही है। निर्माण सामग्री की आपूर्ति पर स्थानीय नेताओं और सिंडिकेट का कब्जा होता था, जो जबल अपनी दरों पर घटिया सामग्री बेचकर वसूली करते थे। स्थानीय क्लबों, व्यापारिक प्रतिष्ठानों और ठेकेदारों को डरा-धमका कर हर महीने अवैध हफ्ता वसूली आम बात थी। सड़कों और निर्माण क्षेत्रों में अवैध रूप से ड्रॉप गेट या बैरिकेड लगाकर अवैध टोल टैक्स वसूला जाता था।

अब तय है कि आम आदमी की उम्मीद यह रहेगी कि इस तरह की गतिविधियों पर अब पूरी तरह से लगाम लग जाए। हार के बाद तृणमूल कांग्रेस के छोटे-बड़े नेता जिस तरह स्थानीय गुंडों पर पार्टी के बड़े नेताओं की शह पर यह सब होने के आरोप लगा रहे हैं उससे साफ है कि पहले जो ऐसे लोग कभी वामपंथी शासन में शह पा रहे थे, वही लोग टी.एम.सी. में आ गए। खतरा यही है कि आवरण बदलकर ये कहीं भाजपा में न आ जाएं।

शुभेंदु अधिकारी जब विपक्ष में थे तो अक्सर टी.एम.सी. के नेताओं पर संगठित अपराध में शामिल होने का आरोप लगाते रहे हैं। पश्चिम बंगाल में नौकरियों में भ्रष्टाचार का मुद्दा भी भाजपा ने उठाया था। राज्य में साल 2016 में स्कूल सेवा आयोग की ओर से आयोजित भर्ती परीक्षा में बड़े पैमाने पर धांधली और घोटाले के आरोप लगे थे। करीब एक साल पहले ही सुप्रीम कोर्ट ने लगभग 25,000 शिक्षकों को भर्ती रद्द कर दी थी। ऐसे में अब भाजपा की सरकार आने के बाद एक स्वच्छ सरकार देना उनके लिए बड़ी चुनौती होगी। खासतौर से तब, जब भाजपा के नेताओं पर भी भ्रष्टाचार के आरोप लगते रहे हैं।

इस सबके बावजूद कहा जा सकता है कि शुभेंदु अधिकारी को और बंगाल में नई-नई सत्ता में आई भाजपा सरकार को उन सब गलतियों से बचना होगा। अपराध से निपटने के लिए उन्होंने योगी मॉडल की शुरुआत तो कर ही दी है। पार्टी कार्यकर्ता तृणमूल या माकपा कार्यकर्ताओं के ढर्रे पर न चलने पाएं, यह देखना सबसे जरूरी होगा। पश्चिम बंगाल के भद्र नागरिकों की शिकायतों पर अगर ईमानदारी से काम हुआ तो इसके नतीजे स्थाई और कारगर होंगे।

srivastvaaaku@gmail.com

Source: <https://www.thehindu.com/news/national/bihar/spotlight-on-midday-meal-in-bihar-in-bihar-a-plate-of-woe/article70990348.ece/amp/>

In Bihar, a plate of woe

A week after a suspected snake was found in a midday meal, students in Bihar's Saharsa district remain too scared to eat lunch at school. Even as teachers, cooks, and education officials insist the food is safe, fear continues to linger among the children and their parents

Published - May 18, 2026 06:09 am IST

Amarnath TewaryAmarnath Tewary

he cooking facility of the NGO which had supplied the food to the school under PM Poshan scheme in Baluaha village of Saharsa district, where over 150 children allegedly fell ill a week ago after consuming midday meal. |

Photo Credit: Amarnath Tewary

Instances of contaminated food served to children under the government-mandated midday meal in Bihar no longer make the media's big-font news. Their regularity numbs the reader into indifference.

On May 7, up to 150 students of a government middle school in Bihar's Baluaha village, in Saharsa district, fell sick and were hospitalised. The children had allegedly spotted a dead baby snake in their watery dal. They were treated at a government hospital and the local Primary Health Centre.

The district administrator suspended and lodged an FIR against two teachers and all the nine cooks of the school. Bharat Kumar Singh, who functions as both the Block Education Officer (BEO) and Block Development Officer (BDO) of Mahishi, says it is the overall responsibility of the staff to make checks. "We have started our Confidence Building Measures (CBMs) for students to eat the meal and situation is gradually improving."

inside of the school kitchen in Baluaha government school. | Photo Credit: Amarnath Tewary

"I, along with the cooks of the school and other teachers taste the food first to build confidence among students, but they have been refusing, saying their parents have told them not to," rues Anupama Kumari Jha, the headmistress.

But parents are nervous. "They have told us not to eat the food, so we carry food from home," says one student, with many echoing her.

Also read: Blame game on over midday meal tragedy

What was earlier the six-days-a-week midday meal scheme in schools was rechristened the Pradhan Mantri Poshan Shakti Nirman scheme in 2021. Bihar's Finance Minister Bijendra Prasad Yadav said in his budget speech for 2026-27, that 68,813 schools in the State and 1.04 crore students from Class 1-8 are covered under the scheme. Children are given hot cooked meals, either cooked on campus or brought in by a non-governmental organisation (NGO).

Over the years, there have been at least five incidents of food contamination in the children's food in Bihar. In February 2025 about 100 children in Lakhisarai district had symptoms of food poisoning after they complained of a lizard in the food. In April 2025 over 100 children in Patna district fell ill and a snake was allegedly found in the food. In September that year, about 85 children fell sick, again after a lizard was found in the cooked vegetable.

Fixing responsibility

For Baluaha village, the base kitchen is located a kilometre away, and is run by an NGO, which says it takes all "hygiene precautions" in preparing food for the school students. "In two blocks of district nearby Mahishi and Nauhatta, our Delhi headquartered NGO supplies food to about 18,000 students every day in over 150 government schools," says the project coordinator Mohd. Ejaz, from Bharat Ratna Dr. Bhim Rao Ambedkar Dalit Utthan Evam Siksha Samiti. He also says 67 staff members, including 16 cooks, work at the organisation to supply food to students in a 10 km radius. The meal is typically served at 9 a.m. during the morning shift of the school in summer.

"Why was the FIR filed against me? It was the NGO that was supplying food," says Jha. The school principal, Vikas Kumar, was on casual leave that day, she says, making her in-charge.

Officials visiting the school in Baluaha village of Saharsa district after over 150 school children fell ill after consuming midday meal. Photo: Special Arrangement

The state government middle school in Baluaha, some 170 kms north from of Patna, was established in 1949, and has 828 students on roll with more girl students than boys. There are 16 teachers and 9 cooks. "That day (May 7) 543 students had come to the school. A school cook, Kaili Devi, asked students not to eat the food, when she saw something in the dal," says Jha.

By then, some of the children had started vomiting and complaining of stomach pain. "We called the local Primary Health Centre (PHC) and the police," she says.

Kaili says, "One of the middle-school students started crying out, 'chilla-chilla' (earthworm). I too spotted it and asked the children not to eat the food."

Saharsa District Programme Officer (MDM), Shalini Jagriti, says the forensics team is determining whether it was snake, earthworm, or something else. "They have taken a sample of the food and the 'creature' for testing," she says.

Jha is grateful the children were all discharged from the healthcare units. Even the parents of children who were not in school on that day gathered within the school campus and shouted slogans against the administration. "We were panicked," says Jha.

One parent says, philosophically, "Life is the only thing which can never be replaced when lost." Another says, angrily that the poor were condemned to eat whatever was handed out. "Poverty is an injustice," he adds.

Shortcomings in the scheme delivery

The Poshan scheme is shared in cost by the Central and State governments in a 60:40 ratio. As of May 2026, it is running in all 38 districts of Bihar.

School cooks with Kaili Devi standing in front, at the school in Baluaha village of Saharsa district, where over 150 students fell sick after consuming the midday meal. | Photo Credit: Amarnath Tewary

Last year in May, after the April incident, when over 100 children had fallen sick after eating contaminated school food, the National Human Rights Commission (NHRC) had issued notice to the Bihar government seeking a detailed report in the matter.

In July 2013, in Dharmasati Gandaman Primary school in Masrakh block of Saran district, 23 students had died after eating contaminated midday meal. The incident had hit national and international headlines, and the school principal Meena Devi, was later sentenced to 17 years in jail, 10 years of which are on charges of culpable homicide not amounting to murder and seven years for criminal negligence, though both sentences were to run consecutively, and not concurrently.

In 2023, Jan Jagriti Shakti Sangathan, a trade union of unorganised sector workers, released a report titled 'Where are the Kids? The Curious Case of Government Schools in Bihar'. It was based on a survey of 81 schools in two districts in North Bihar, and offers glimpses into the state of education in the rural parts of the State. "While it is not clear why NGOs are involved in the first place, the lack of a uniform system for cooking midday meals causes confusion. There have been numerous reports from Bihar where children have fallen sick after eating the midday meal..." it says.

amarnath.tewary@thehindu.co.in

Published - May 18, 2026 06:09 am IST

Source: <https://www.orissapost.com/music-unites-hearts-heals-minds-governor/>

Music unites hearts, heals minds: Governor

Post News Network Updated: May 17th, 2026, 10:48 IST in Metro, Top Stories

Bhubaneswar: Governor Hari Babu Kambhampati Saturday said music possesses the unique ability to unite hearts, heal minds and strengthen human values, while transcending barriers of language, religion, region and generation.

Addressing the 103rd birth anniversary celebration of legendary Odissi music maestro Pandit Balakrushna Dash at Rabindra Mandap here, the Governor described the iconic musician as a “timeless institution” whose contribution enriched the cultural soul of Odisha and inspired generations of artistes and music lovers.

Paying rich tributes to the legendary composer and singer, the Governor said Pandit Balakrushna Dash made unparalleled contributions to Odissi classical music, devotional compositions, Chhanda, Champu, folk traditions and Odia cinema.

He noted that the maestro transformed Odissi music into a vibrant and structured classical tradition and carried Odisha’s rich musical heritage beyond the boundaries of the state.

The Governor said, “Music has the unique ability to unite hearts, heal minds and strengthen human values, while transcending barriers of language, religion, region and generation.” He said Dash successfully combined the depth of classical music with emotional accessibility, making Odissi music popular among the masses through cinema, radio and public performances.

Through All India Radio, Cuttack, he carried the melodies of Odisha into countless homes, while as a guru at Utkal Sangeet Mahavidyalaya, he nurtured generations of musicians who continue to uphold the distinctive “Balakrushna Dash style”.

Highlighting the relevance of the maestro’s life for younger generations, the Governor said his journey symbolised dedication, humility, discipline and deep respect for cultural roots. He urged the youth to remain proud of India’s heritage while striving for innovation and excellence in a rapidly changing world.

The event also marked the 34th Annual Day celebration of Sangeet Sudhakar Balakrushna Dash Foundation. The Governor also congratulated internationally acclaimed classical dancer Padma Vibhushan Sonal Mansingh, who was conferred the prestigious “Sangeet Sudhakar Balakrushna Dash Memorial Award 2026”, along with other distinguished awardees.

He commended the foundation for its efforts in preserving and promoting Odissi music through festivals, archival work, training programmes and scholarships.

Among others, National Human Rights Commission Member Justice BR Sarangi, OSSSC Chairman Lalit Das, NALCO Executive Director (HR) Ashutosh Rath and legendary dancer Sonal Mansingh also addressed the gathering

and highlighted the invaluable contribution of Pandit Balakrushna Dash to Odissi music and Odisha's cultural heritage.

Foundation's president Manoranjan Panigrahi and secretary Guru Ramahari Das were also present on the occasion.

Source: <https://www.msn.com/en-in/news/India/will-take-care-of-pushpa-suvendu-in-abhishek-lair-after-unseating-didi/ar-AA23mFyo?apiversion=v2&domshim=1&noservercache=1&noservertelemetry=1&batchservertelemetry=1&renderwebcomponents=1&wcs>

Will take care of Pushpa: West Bengal CM Suvendu Adhikari in Abhishek lair after unseating Didi
Story by Rohit Khanna and Monotosh Chakraborty • 1d •

KOLKATA: CM Suvendu Adhikari took his first political programme outside his own constituencies to Falta in South 24 Parganas on Saturday — squarely in Abhishek Banerjee's Diamond Harbour parliamentary constituency — in a pointed move at a Trinamool stronghold days after he unseated former CM Mamata Banerjee from Bhowanipore.

Falta goes for a repoll on May 21 after widespread allegations of electoral malpractice and the high-voltage "Pushpa-Singham" confrontation between outgoing Trinamool MLA Jahangir Khan and EC-appointed poll observer Ajay Pal Sharma.

Addressing a rally, Adhikari took direct aim at Jahangir, who had compared himself to the blockbuster film Pushpa's smuggler-turned-strongman. "Where is that Pushpa — the dacoit? He is not seen anywhere now. The National Human Rights Commission declared 19 persons as notorious criminals in 2021. Jahangir was one of them. Leave him to me. I will take care of him," the CM said.

Ahead of the rally, police arrested Saidul Khan, a close aide of Jahangir and Trinamool's Falta vice-president, on multiple charges including death threats.

Adhikari also trained his guns on Trinamool's alleged corruption, citing "Leaps and Bounds" — a company he claimed has 24 properties in Kolkata and a "palatial office at Amtala" — and announcing that police would register complaints against anyone found to have siphoned funds from central schemes including PM Kisan, Krishak Bandhu and Amphan relief.

"The accused will be put behind bars," he said. He added that call records and WhatsApp chats of three IPS officers who were suspended for allegedly mishandling the RG Kar rape-murder case probe — Vineet Goyal, Indira Mukherjee and Abhishek Gupta — were being examined. "You will get to see the misdeeds of the previous govt once these are investigated," he said.

Urging voters to ensure a peaceful repoll, Adhikari said BJP MLAs would facilitate the return of those displaced by post-poll violence, provided they were not accused of violence themselves. He also assured that all complaints of torture over the past five years would be registered. "None of the 20 BJP-governed states have any record of violence during polls," he said. He will return to Falta for a full day of campaigning on Tuesday.

Source: <https://english.punjabkesari.com/india/bhojshala-verdict-sparks-fresh-hope-for-revival-of-vidishas-vijay-mandir-says-nhrcc-priyank-kanoongo/>

Home » India » Bhojshala verdict sparks fresh hope for revival of Vidisha's Vijay Mandir, says NHRC's Priyank Kanoongo

Bhojshala verdict sparks fresh hope for revival of Vidisha's Vijay Mandir, says NHRC's Priyank Kanoongo

By: IANS

On: Sunday, May 17, 2026 10:18 AM

Vidisha (Madhya Pradesh), May 17 (IANS) National Human Rights Commission (NHRC) member Priyank Kanoongo welcomed the Madhya Pradesh High Court's verdict declaring the Kamal Maula Mosque, also known as Bhojshala, a temple, and said the judgment has renewed hopes for the revival of the centuries-old Vijay Surya Mandir in Vidisha as well.

The Indore Bench of the Madhya Pradesh High Court recently redefined the legal status of the Bhojshala complex in Dhar, ruling that the site is a temple and that the Hindu community's right to worship there had never ceased historically.

In a major ruling delivered on Friday, the division bench of Justice Vijay Kumar Shukla and Justice Alok Awasthi set aside decades of administrative arrangements and compromises surrounding the disputed site.

Reacting to the verdict on Saturday, Kanoongo said the judgment reflects what he described as India's ongoing "cultural revival" and linked it to other major religious developments in the country.

Speaking to the reporters, Kanoongo said, "We are the people of that fortunate generation who are witnessing the cultural revival of India with their own eyes. We have seen how Prime Minister Narendra Modi ensured that the struggle of 500 years in Ayodhya comes to an end by building a huge Ram Temple."

He further stated that people across the country are reconnecting with what he termed their historical and cultural legacy.

"People of India are experiencing the glory of their glorious past; all these things are happening. This Bhojshala verdict has also raised hopes that the Goddess Saraswati idol be brought back and we could again start worshipping there," he said.

The remarks have also brought renewed attention to the long-standing dispute surrounding the Vijay Surya Mandir in Vidisha, a centuries-old structure where members of the Hindu community have traditionally gathered outside locked gates during the festival of Nag Panchami to offer prayers.

In 2024, when permission was sought to enter the premises and conduct rituals inside the structure during the festival, the Archaeological Survey of India (ASI) stated that the monument was officially registered as the Bijamandal Mosque and not a temple. The ASI cited a gazette notification issued in 1951 to support its position

regarding the site's legal and historical status.

Referring to the Vidisha dispute, Kanoongo said the Bhojshala judgment has strengthened expectations among those seeking recognition of the Vijay Surya Mandir's historical identity.

"This verdict has also made us optimistic that Vidisha's Vijay Temple will also achieve this success. I pray to Mahakal that these wishes are fulfilled," he said.

The issue surrounding the Vidisha structure has continued to generate debate among local representatives and religious groups. Vidisha MLA Mukesh Tondon and several Hindu organisations have been demanding a fresh and detailed archaeological survey of the site.

Those supporting the demand for a new survey argue that a comprehensive archaeological examination is necessary to determine the true historical character of the monument and clarify its original purpose and usage.

The debate has also gained momentum in the backdrop of recent judicial interventions and legal proceedings in several temple-mosque disputes across the country. Following developments in such cases, Hindu organisations have expressed hope that disputed religious sites would undergo renewed legal and historical scrutiny.

The Bhojshala ruling by the Madhya Pradesh High Court is being viewed by several groups as a landmark judgment that could influence future discussions around historically contested religious sites in the country.

-IANS

Source: https://jantaserishta.com/local/chhattisgarh/medical-shops-will-remain-closed-on-may-20-4722768#google_vignette

राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के विशेष प्रतिवेदक सुभाष चन्द्र ने जशपुर में वृद्धाश्रम-नशामुक्ति केंद्र का किया निरीक्षण
Nilmani Pal17 May 2026 12:58 PM

जशपुर। राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग, नई दिल्ली के विशेष प्रतिवेदक सुभाष चन्द्र द्वारा जशपुर जिले में संचालित वृद्धाश्रम एवं नशामुक्ति केंद्र का निरीक्षण कर वहां उपलब्ध व्यवस्थाओं, सुविधाओं एवं सेवाओं का जायजा लिया गया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने हितग्राहियों से संवाद कर उनकी दिनचर्या, स्वास्थ्य सुविधाओं तथा पुनर्वास संबंधी व्यवस्थाओं की जानकारी प्राप्त की। विशेष प्रतिवेदक सुभाष चन्द्र ने नशामुक्ति केंद्र में उपचाररत हितग्राहियों को नशे से दूर रहकर स्वस्थ, अनुशासित एवं सकारात्मक जीवनशैली अपनाने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने कहा कि नियमित दिनचर्या, मानसिक संतुलन और सामाजिक सहभागिता व्यक्ति को नई दिशा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। उन्होंने हितग्राहियों को इनडोर एवं आउटडोर गेम्स, योग, मनोरंजक एवं रचनात्मक गतिविधियों में सक्रिय रूप से भाग लेने के लिए भी प्रोत्साहित किया, ताकि उनमें आत्मविश्वास बढ़े और समाज की मुख्यधारा से जुड़ने में सहायता मिल सके। निरीक्षण के दौरान समाज कल्याण विभाग के अधिकारियों एवं कर्मचारियों ने केंद्र में संचालित गतिविधियों, पुनर्वास कार्यक्रमों तथा हितग्राहियों को दी जा रही सुविधाओं की जानकारी दी। इस अवसर पर विभागीय अधिकारी-कर्मचारी उपस्थित रहे।

Source: <https://www.joharlive.com/news/jail-superintendent-impregnates-female-inmate-babulal-marandi-levels-serious-allegation-writes-open-letter-to-cm/>

जेल सुपरिंटेंडेंट ने महिला कैदी को कर दिया गर्भवती”, बाबूलाल मरांडी का गंभीर आरोप, सीएम को लिखी खुली चिट्ठी
Rudra ThakurBy Rudra ThakurMay 17, 2026

Ranchi : झारखंड की राजनीति में उस समय हलचल तेज हो गई, जब नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने सीएम हेमंत सोरेन को पत्र लिखकर रांची स्थित बिरसा मुंडा सेंट्रल में एक महिला कैदी के साथ कथित यौन शोषण का गंभीर आरोप लगाया। मरांडी ने दावा किया है कि जेल सुपरिंटेंडेंट द्वारा महिला कैदी का लगातार शारीरिक शोषण किया गया, जिससे वह गर्भवती हो गई। उन्होंने मामले को दबाने और सबूत मिटाने की भी आशंका जताई है। नेता प्रतिपक्ष ने अपने पत्र में कहा है कि यह घटना बेहद शर्मनाक और मानवता को झकझोर देने वाली है। उन्होंने आरोप लगाया कि न्यायिक अभिरक्षा में बंद एक असहाय महिला कैदी का जेल के अंदर शोषण किया गया और अब पूरे मामले को दबाने की कोशिश की जा रही है।

सबूत मिटाने की साजिश का आरोप

बाबूलाल मरांडी ने आरोप लगाया कि पीड़ित महिला कैदी को बीमारी और इलाज के नाम पर गुप्त स्थानों तथा अस्पतालों में ले जाया जा रहा है, ताकि गर्भ और फॉरेंसिक साक्ष्यों को नष्ट किया जा सके। उन्होंने कहा कि इस पूरे मामले में जेल आईजी की भूमिका भी संदिग्ध है और वे दोषी अधिकारियों को बचाने में लगे हुए हैं। पत्र में यह भी कहा गया है कि जेल के अंदर की गतिविधियों और अधिकारियों के आवागमन के गवाह रहे कर्मचारियों को योजनाबद्ध तरीके से इधर-उधर स्थानांतरित किया जा रहा है, ताकि वे चुप रहें और मामला बाहर न आ सके।

“सरकार की जवाबदेही तय हो”

मरांडी ने मुख्यमंत्री को चेतावनी देते हुए कहा कि यदि आरोपित जेल सुपरिंटेंडेंट और जेल आईजी पर तत्काल कार्रवाई नहीं हुई, तो यह माना जाएगा कि सरकार के शीर्ष स्तर पर भी इस मामले को संरक्षण मिल रहा है। उन्होंने कहा कि राज्य की प्रशासनिक व्यवस्था पूरी तरह विफल हो चुकी है और जेलों के अंदर अपराधियों को संरक्षण दिया जा रहा है। उन्होंने अपने पत्र में लिखा कि बिरसा मुंडा केंद्रीय कारागार के भीतर लंबे समय से एक संगठित भ्रष्ट तंत्र काम कर रहा है। सच को दबाने और गवाहों को चुप कराने के लिए पैसे बांटे जा रहे हैं तथा प्रशासनिक दबाव बनाया जा रहा है।

आयोगों और अदालतों से हस्तक्षेप की मांग

नेता प्रतिपक्ष ने राष्ट्रीय महिला आयोग, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट से मामले में संज्ञान लेने की मांग की है। उन्होंने झारखंड की जेलों में महिलाओं के कथित उत्पीड़न की निष्पक्ष जांच कराने और दोषियों पर सख्त कार्रवाई की अपील की है। हालांकि, इस मामले में राज्य सरकार या जेल प्रशासन की ओर से अब तक कोई आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है। आरोपों की स्वतंत्र पुष्टि भी फिलहाल नहीं हो सकी है।

Source: <https://www.agniban.com/bengal-cm-shubhendus-first-meeting-in-falta-by-election-said-where-is-pushpa-you-are-not-visible-now/>

बंगाल: फाल्टा उपचुनाव में CM शुभेन्दु की पहली सभा.... बोले- कहां है पुष्पा, अब दिखाई नहीं दे रहा?
May 17, 2026 AGNIBAN

कोलकाता। पश्चिम बंगाल (West Bengal.) के नवनिर्वाचित मुख्यमंत्री शुभेन्दु अधिकारी (Chief Minister Shubhendu Adhikari) ने डायमंड हार्बर लोकसभा क्षेत्र के तहत आने वाली फाल्टा विधानसभा सीट पर होने वाले उपचुनाव (Falta By-Election) से पहले तृणमूल कांग्रेस (TMC) और अभिषेक बनर्जी (Abhishek Banerjee.) पर करारा हमला बोला है। शनिवार को भाजपा उम्मीदवार देबांगशु पोंडा के समर्थन में फाल्टा में एक बड़ी रैली को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने सुरक्षा, कानून-व्यवस्था और भ्रष्टाचार को लेकर कई बड़े एलान किए। मुख्यमंत्री बनने के बाद इस क्षेत्र में यह उनकी पहली जनसभा थी।

शुभेन्दु अधिकारी ने टीएमसी के फाल्टा उम्मीदवार जहांगीर खान (Jahangir Khan) को आड़े हाथों लेते हुए उन्हें घोषित कुख्यात अपराधी करार दिया। उन्होंने कहा, “2019 के चुनाव बाद हुई हिंसा पर राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (NHRC) ने राज्य के 19 सबसे कुख्यात अपराधियों की सूची जारी की थी। भतीजे के संरक्षण में पलने वाला यह जहांगीर खान उसी सूची में शामिल था। अब इस तथाकथित ‘पुष्पा’ को मेरे भरोसे छोड़ दीजिए, जो अब कहीं दिखाई भी नहीं दे रहा है। वह अब मेरी जिम्मेदारी है और मैं खुद उसका मामला देखूंगा।”

क्या था ‘पुष्पा’ और ‘सिंघम’ का विवाद?

चुनाव आयोग द्वारा नियुक्त पुलिस पर्यवेक्षक 2011 बैच के यूपी कैडर के आईपीएस अधिकारी अजय पाल शर्मा (IPS Ajay PAI Sharma) ने मतदाताओं को धमकाने की शिकायत के बाद जहांगीर खान के घर और दफ्तर का दौरा किया था। इस पर टीएमसी उम्मीदवार जहांगीर खान ने पलटवार करते हुए कहा था कि “अगर वह सिंघम हैं, तो मैं ‘पुष्पा’ हूँ।” मुख्यमंत्री ने इसी बयान पर तंज कसा है।

मुख्यमंत्री शुभेन्दु अधिकारी ने आरोप लगाया कि जब से बंगाल के राजनीतिक पटल पर ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी का उदय हुआ है, तब से पिछले एक दशक में डायमंड हार्बर और फाल्टा के लोग स्वतंत्र रूप से अपने मताधिकार का प्रयोग नहीं कर पाए हैं।

उन्होंने जनता को आश्वस्त करते हुए कहा, “अब बंगाल का परिदृश्य बदल चुका है। फाल्टा विधानसभा सीट पर 21 मई 2026 को होने वाला पुनर्मतदान यहां के लोगों को उनका लोकतांत्रिक अधिकार वापस दिलाएगा। मैं फाल्टा के मतदाताओं से अपील करता हूँ कि वे भाजपा उम्मीदवार को 1 लाख से अधिक वोटों के अंतर से विजयी बनाएं।” इसके साथ ही उन्होंने कार्यकर्ताओं से कानून अपने हाथ में न लेने और शांतिपूर्ण मतदान सुनिश्चित करने की अपील की।

फाल्टा में दोबारा चुनाव क्यों?

चुनाव आयोग ने फाल्टा में 29 अप्रैल को हुए मतदान को ईवीएम (EVM) से छेड़छाड़ और मतदाताओं को डराने-धमकाने जैसी गंभीर अनियमितताओं की शिकायतों के बाद रद्द कर दिया था।

भ्रष्टाचार के मुद्दे पर अभिषेक बनर्जी को घेरते हुए मुख्यमंत्री ने बड़ा खुलासा किया। उन्होंने कहा कि उन्हें ‘लीप्स एंड बाउंड्स’ (Leaps and Bounds) कंपनी से जुड़ी संपत्तियों की फाइलें मिल चुकी हैं। उन्होंने कहा, “मैंने कोलकाता नगर निगम से फाइलें मांगी थीं। अब मेरे पास दक्षिण 24 परगना जिले के आमताला में एक आलीशान दफ्तर सहित इस कंपनी की 24 संपत्तियों की पूरी सूची और विवरण है। बहुत जल्द इन सभी संपत्तियों के खिलाफ गहन जांच शुरू की जाएगी।”

5 साल पुराने मामले भी खुलेंगे

चुनाव के बाद डर के मारे पलायन कर चुके लोगों की वापसी को लेकर मुख्यमंत्री ने कड़ा और स्पष्ट रुख अपनाया। उन्होंने कहा कि सरकार सभी की सुरक्षित वापसी सुनिश्चित करेगी, लेकिन यह सशर्त होगी। उन्होंने कहा, “2021 की चुनाव बाद हुई हिंसा में भाजपा के 57 कार्यकर्ताओं की हत्या हुई थी और 12,500 एफआईआर दर्ज की गई थीं। यदि इन फरार लोगों में से किसी का भी नाम उन एफआईआर में आरोपी के रूप में दर्ज है, तो उन्हें घर लौटने की अनुमति नहीं दी जाएगी। हम उन्हें बालों से घसीटकर जेल की सलाखों के पीछे भेजेंगे।”

मुख्यमंत्री ने पुलिस को स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि भले ही राजनीतिक अपराध 5 साल या उससे अधिक पुराने क्यों न हों, उनके खिलाफ शिकायतें दर्ज कर अपराधियों को तुरंत जेल भेजा जाए।

धार्मिक भावनाओं का सम्मान

अक्टूबर 2025 में दक्षिण 24 परगना के काकद्वीप में मां काली की खंडित मूर्ति को पुलिस द्वारा कैदी वैन में रखने के विवाद का जिक्र करते हुए सीएम ने कहा, "जिस पुलिस अधिकारी ने मां काली की मूर्ति को जेल वैन के अंदर रखा, उसके लिए बंगाल में कोई जगह नहीं है। हिंदू देवी-देवताओं के अपमान और मूर्तियों को नुकसान पहुंचाने से जुड़ी सभी पुलिस फाइलें दोबारा खोली जाएंगी।"

विशेष विकास पैकेज का एलान

अपने संबोधन के अंत में मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने फाल्ता की जनता के लिए भाजपा के चुनावी घोषणा-पत्र के वादों से अलग एक विशेष विकास पैकेज देने की भी घोषणा की। उन्होंने कहा कि जनता ने उन्हें सत्ता की कुर्सी सिर्फ बैठने के लिए नहीं बल्कि न्याय के लिए सौंपी है और वे राज्य में न्याय का शासन स्थापित करके रहेंगे।

Source: <https://navbharatlive.com/west-bengal/west-bengal-cm-suvendu-adhikari-attack-on-tmc-leader-jahangir-khan-falta-by-election-1738217.html>

Hindi News »West Bengal » West Bengal Cm Suvendu Adhikari Attack On Tmc Leader Jahangir Khan Falta By Election

कहां छुपा है पुष्पा, सामने क्यों नहीं आ रहा? IPS अजय पाल से टकराने वाले जहांगीर पर सुवेंदु अधिकारी का तंज
Suvendu Adhikari: एक बड़ी रैली को संबोधित करते हुए सीएम सुवेंदु ने सुरक्षा, कानून-व्यवस्था और भ्रष्टाचार को लेकर कई बड़ी घोषणाएं किए।
मुख्यमंत्री के रूप में इस क्षेत्र में उनकी यह पहली जनसभा थी।
Written By: मनोज आर्या Updated On: May 17, 2026 | 06:43 PM

Suvendu Adhikari On Jahangir Khan: पश्चिम बंगाल के नए मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने तृणमूल कांग्रेस और अभिषेक बनर्जी पर करारा हमला बोला है। डायमंड हार्बर लोकसभा क्षेत्र के तहत आने वाली फाल्टा विधानसभा सीट पर होने वाले उपचुनाव (Falta By-Election) से पहले वह शनिवार को एक जनसभा को संबोधित कर रहे थे। जहां से भाजपा उम्मीदवार देबांग्शु पोंडा चुनावी मैदान में खड़े हैं।

एक बड़ी रैली को संबोधित करते हुए सीएम सुवेंदु ने सुरक्षा, कानून-व्यवस्था और भ्रष्टाचार को लेकर कई बड़ी घोषणाएं किए। मुख्यमंत्री के रूप में इस क्षेत्र में उनकी यह पहली जनसभा थी।

पुष्पा' को मेरे भरोसे छोड़ दीजिए- सीएम
फाल्टा सीट से टीएमसी उम्मीदवार जहांगीर खान पर निशाना साधते हुए सुवेंदु अधिकारी ने उन्हें कुख्यात अपराधी करार दिया। मुख्यमंत्री ने कहा कि 2019 के चुनाव बाद हुई हिंसा पर राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (NHRC) ने राज्य के 19 सबसे कुख्यात अपराधियों की सूची जारी की थी। सुवेंदु अधिकारी ने आगे कहा कि भतीजे (अभिषेक बनर्जी) के संरक्षण में पलने वाला यह जहांगीर खान उसी सूची में शामिल था। अब इस तथाकथित 'पुष्पा' को मेरे भरोसे छोड़ दीजिए, जो अब कहीं दिखाई भी नहीं दे रहा है। वह अब मेरी जिम्मेदारी है और मैं खुद उसका मामला देखूंगा।

अगर वह सिंघम हैं, तो मैं पुष्पा हूँ
चुनाव आयोग द्वारा नियुक्त पुलिस पर्यवेक्षक 2011 बैच के यूपी कैडर के आईपीएस अधिकारी अजय पाल शर्मा ने मतदाताओं को धमकाने की शिकायत के बाद जहांगीर खान के घर और दफ्तर का दौरा किया था। इस पर टीएमसी उम्मीदवार जहांगीर खान ने पलटवार करते हुए कहा था कि "अगर वह सिंघम हैं, तो मैं 'पुष्पा' हूँ।" मुख्यमंत्री ने इसी बयान पर तंज कसा है।

मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने आरोप लगाया कि जब से बंगाल के राजनीतिक पटल पर ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी का उदय हुआ है, तब से पिछले एक दशक में डायमंड हार्बर और फाल्टा के लोग स्वतंत्र रूप से अपने मताधिकार का प्रयोग नहीं कर पाए हैं।

'अब बंगाल की स्थिति बदल चुका है'

उन्होंने जनता को आश्वस्त करते हुए कहा कि अब बंगाल की स्थिति बदल चुका है। फाल्टा विधानसभा सीट पर 21 मई 2026 को होने वाला पुनर्मतदान यहां के लोगों को उनका लोकतांत्रिक अधिकार वापस दिलाएगा। मैं फाल्टा के मतदाताओं से अपील करता हूँ कि वे भाजपा उम्मीदवार को 1 लाख से अधिक वोटों के अंतर से विजयी बनाएं। इसके साथ ही उन्होंने कार्यकर्ताओं से कानून अपने हाथ में न लेने और शांतिपूर्ण मतदान सुनिश्चित करने की अपील की।

Source: <https://www.cgmp.co.in/national-human-rights-commissions-special-rapporteur-subhash-chandra-inspected-the-old-age-home-and-de-addiction-center-in-jashpur/162031/>

राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के विशेष प्रतिवेदक सुभाष चन्द्र ने जशपुर में वृद्धाश्रम एवं नशा मुक्ति केंद्र का किया निरीक्षण
By Dipesh Kushwaha - May 17, 2026

रायपुर: राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग, नई दिल्ली के विशेष प्रतिवेदक सुभाष चन्द्र द्वारा जशपुर जिले में संचालित वृद्धाश्रम एवं नशामुक्ति केंद्र का निरीक्षण कर वहां उपलब्ध व्यवस्थाओं, ओं सुविधाओं एवं सेवाओं का जायजा लिया गया। निरीक्षण के दौरान उन्होंनेनेहों नेहितग्राहियों से संवाद कर उनकी दिनचर्या, स्वास्थ्य सुविधाओं तथा पुनर्वास संबंधी व्यवस्थाओं की जानकारी प्राप्त की। विशेष प्रतिवेदक सुभाष चन्द्र ने नशामुक्ति केंद्र में उपचाररत हितग्राहियों को नशे से दूर रहकर स्वस्थ, अनुशासित एवं सकारात्मक जीवनशैली अपनाने के लिए प्रेरित किया। उन्होंनेनेहों नेकहा कि नियमित दिनचर्या, मानसिक संतुलन और सामाजिक सहभागिता व्यक्ति को नई दिशा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। उन्होंनेनेहों नेहितग्राहियों को इनडोर एवं आउटडोर गेम्स, योग, मनोरंजक एवं रचनात्मक गतिविधियों में सक्रिय रूप से भाग लेने के लिए भी प्रोत्साहित किया, ताकि उनमें आत्मविश्वास बढ़े और समाज की मुख्यधारा से जुड़ने में सहायता मिल सके।

निरीक्षण के दौरान समाज कल्याण विभाग के अधिकारियों एवं कर्मचारियों ने केंद्र में संचालित गतिविधियों, यों पुनर्वास कार्यक्रमों तथा हितग्राहियों को दी जा रही सुविधाओं की जानकारी दी। इस अवसर पर विभागीय अधिकारी-कर्मचारी उपस्थित रहे।

Source: <https://m.dailyhunt.in/news/india/hindi/aapka+rajasthan-epaper-aaprajs/siem+suwendu+adhikari+ka+bada+sanket+mistar+nephyu+ki+sampattiyo+ki+janch+ki+chetavani-newsid-n712513208>

सीएम सुवेंदु अधिकारी का बड़ा संकेत, 'मिस्टर नेफ्यू' की संपत्तियों की जांच की चेतावनी
आपका राजस्थान 1 day ago

कोलकाता, 16 मई (आईएनएस)। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री सुवेंदु अधिकारी ने शनिवार को बिना नाम लिए तृणमूल कांग्रेस के एक शीर्ष नेता से जुड़ी कथित कंपनी की संपत्तियों की जांच शुरू करने का संकेत दिया।

दक्षिण 24 परगना जिले के डायमंड हार्बर उपखंड के अंतर्गत फाल्टा विधानसभा क्षेत्र में एक जनसभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने उस नेता को बार-बार "मिस्टर नेफ्यू" कहकर संबोधित किया। यहां 21 मई को पुनर्मतदान होना है।

मुख्यमंत्री ने कहा, "मिस्टर नेफ्यू, मैं कल ही कोलकाता नगर निगम से आपकी कंपनी की संपत्तियों की पूरी सूची लेकर आया हूं। कंपनी की कोलकाता में 24 संपत्तियां हैं। दक्षिण 24 परगना के आमतला में महल जैसा कार्यालय भी है।"

सभा को संबोधित करते हुए सुवेंदु अधिकारी ने अगस्त 2024 के आरजी कर रेप और मर्डर मामले में पूर्व कोलकाता पुलिस आयुक्त विनीत गोयल तथा पूर्व डीसी इंदिरा मुखर्जी और अभिषेक गुप्ता को निलंबित किए जाने के अपने शुक्रवार के ऐलान का भी जिक्र किया।

उन्होंने कहा, "इस मामले में पहले ही तीन आईपीएस अधिकारियों को निलंबित किया जा चुका है और उनके खिलाफ विभागीय जांच शुरू हो चुकी है। जब जांच एजेंसियां उनके कॉल रिकॉर्ड और व्हाट्सएप चैट सामने लाएंगी, तब पिछली सरकार की असल करतूतें उजागर होंगी। लोगों को पता चलेगा कि पिछली सरकार कितनी नीचे तक गिर गई थी।"

मुख्यमंत्री ने फाल्टा पुनर्मतदान में तृणमूल कांग्रेस उम्मीदवार जहांगीर खान को भी चेतावनी दी।

उन्होंने कहा, "2021 के चुनाव बाद हुई हिंसा के बाद राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने हिंसा में शामिल 199 आरोपियों को कुख्यात अपराधी घोषित किया था। उनमें एक जहांगीर भी था। पुनर्मतदान खत्म होने दीजिए, उसके पुराने कृत्यों के लिए कानून के तहत उचित कार्रवाई सुनिश्चित करूंगा।"

अधिकारी ने यह भी कहा कि उन्होंने दक्षिण 24 परगना पुलिस को 2021 की चुनाव बाद हिंसा के पीड़ितों और हिंसा फैलाने वालों की सूची तैयार करने का निर्देश दिया है।

उन्होंने कहा, "एक भी गुंडा घर में नहीं रहेगा। महिलाओं पर अत्याचार करने वाले भी बख्खे नहीं जाएंगे।"

--आईएनएस

डीएससी

Source: <https://www.jagran.com/uttarakhand/dehradun-city-dehradun-fake-cid-officer-busted-in-ssc-exam-cheating-racket-40241876.html>

उत्तराखंड में फर्जी सीआईडी अफसर का हाईटेक नकल रैकेट बेनकाब, तैयारी और सेटअप देख पुलिस हैरान

By Soban Singh Edited By: Nirmala Bohra

Updated: Sun, 17 May 2026 09:11 AM (IST)

एसटीएफ ने देहरादून में एसएससी कांस्टेबल जीडी परीक्षा में नकल की साजिश रचने वाले एक हाईटेक अपराधी को पकड़ा है।

सोबन सिंह गुसाईं, देहरादून। स्टाफ सलेक्शन कमीशन (एसएससी) की कांस्टेबल जीडी आनलाइन परीक्षा में नकल की साजिश रचने वाले आरोपित का हाईटेक नेटवर्क सामने आने के बाद पुलिस भी हैरान है।

खुद को सीआईडी अधिकारी बताकर रौब झाड़ने वाला आरोपित ईश्वरी प्रसाद उर्फ इंद्रजीत शर्मा उर्फ इंद्र तकनीक का इस्तेमाल कर बड़े स्तर पर नकल कराने की तैयारी में था।

फर्जी पहचान पत्र बरामद

एसटीएफ को आरोपित के पास से एक फर्जी पहचान पत्र बरामद हुआ, जिस पर क्राइम इन्वेस्टिगेशन डिटेक्टिव लिखा था। इस कार्ड में क्यूआर कोड भी लगा था, जिसे स्कैन करते ही एक वेबसाइट खुल जाती थी। वेबसाइट पर भ्रष्टाचार विरोधी संदेश, साइबर क्राइम जागरूकता, प्राइवेट डिटेक्टिव सेवाएं और पुलिस मित्र जैसे कई भ्रामक दावे किए गए थे, जिससे लोगों को उसकी पहचान असली लग सके।

इतना ही नहीं, वेबसाइट पर तथाकथित क्राइम इन्वेस्टिगेशन डिटेक्टिव ट्रस्ट के नाम से कई गतिविधियों का विवरण भी दिया गया था। साथ ही, राष्ट्रीय महिला आयोग, केंद्रीय सतर्कता आयोग और राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग जैसे संस्थानों के नाम से फर्जी प्रमाणपत्र भी अपलोड किए गए थे, जिससे उसकी विश्वसनीयता बढ़ाई जा सके।

पुलिस के अनुसार, आरोपित इस पूरे डिजिटल सेटअप का इस्तेमाल लोगों को प्रभावित करने और अपने अवैध नेटवर्क को मजबूत करने के लिए करता था। वह खुद को जांच एजेंसियों से जुड़ा बताकर लोगों को डराता-धमकाता भी था। फिलहाल पुलिस आरोपित के नेटवर्क, उसके सहयोगियों और इस रैकेट के विस्तार की गहराई से जांच कर रही है। अधिकारियों का कहना है कि इस मामले में और भी बड़े खुलासे हो सकते हैं।

पूछताछ में सामने आ सकता है बड़ा नेटवर्क

एसटीएफ की ओर से गिरफ्तार किए गए आरोपित से पूछताछ में बड़े नेटवर्क का पर्दाफाश होने की संभावना है। 18 मई से शुरू होने जा रही कांस्टेबल जीडी आनलाइन की बड़ी परीक्षा है, जोकि 30 मई तक तीन शिफ्टों में होनी है। आरोपित के संपर्क में और कौन-कौन लोग हैं, इसका पता पूछताछ के बाद ही लग सकेगा। बताया जा रहा है कि आरोपित ब्लूटूथ, रिमोट एक्सेस व कैमरों का एक्सेस प्राप्त कर नकल कराने की योजना बना रहे थे।

सेंटर के इर्द गिर्द भी घूम रही शक की सुई

नेहरू ग्राम स्थित जिस सेंट्रल जॉस एकेडमी केंद्र को एसटीएफ ने सील किया है उसके आसपास भी एसटीएफ की शक की सुई घूम रही है। एसटीएफ की अब तक हुई जांच में अभी तक सेंटर का मालिक सामने नहीं आ पाया है। बताया जा रहा है कि सेंटर का मालिक कोई और है जबकि एग्जीमेंट किसी और के नाम से है।

DATE	CHANNEL	TIME	DETAILS	DURATION	PROGRAM	AUTHOR	PERSONALITY
17.05.2026	News State	19:00	विदिशा मेडिकल कॉलेज के भर्ती और वेतन बिल से जुड़े मामले में NHRC ने सख्त रुख अपनाया है। आरोप है कि 400 कर्मचारियों की जगह 600 कर्मचारियों के वेतन बिल लगाए गए।	07:53 Min	Breaking News	abc	
17.05.2026	News18 Bihar Jharkhand	15:00	Pratik Yadav Death: प्रतीक यादव की मौत से जुड़ी खबरों को लेकर लगातार कई सवाल उठ रहे हैं। इस मामले में अब तक सामने आई जानकारी के आधार पर स्थिति स्पष्ट करने की कोशिश की जा रही है। स्थानीय प्रशासन और संबंधित सूत्रों के अनुसार मामले की जांच जारी है और पुलिस सभी पहलुओं की बारीकी से पड़ताल कर रही है। अभी तक किसी भी निष्कर्ष की आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है।	03:55 Min	Breaking News	Abc	
17.05.2026	News18 J&K	17:47	Dr Jitendra Singh Says Women in J&K Are Excelling Under PM Modi's Leadership -Union Minister Dr Jitendra Singh said that the last 12 years under Prime Minister Narendra Modi have significantly raised the aspirations and confidence of women across India, including Jammu and Kashmir. Speaking during the NCW's Shakti Samvad programme in Srinagar, he highlighted how girls from J&K are excelling in civil services, IIT-JEE and other competitive	03:46 Min	Breaking News	Abc	
17.05.2026	Kalinga TV	14:14	DGP Y.B. Khurania Holds Statewide Police Briefings Following Mob Lynching Case	06:33 Min	Breaking News	Abc	

17.05.2026	24 News	13:25	<p>Walayar mob lynching; 7 accused granted bail</p> <p>-The sixth accused in the case, K Vinod, committed suicide the other day. The police have not yet filed a charge sheet against the accused in the court. In addition, the accused were in remand for 90 days. The court granted natural bail to the accused based on both of these. Ram Narayan Baghel, a native of Chhattisgarh, was killed in a mob attack in East Attapalla on December 17, 2025. Ram Narayan Baghel, a guest worker from Jharkhand, was beaten to death by a gang of RSS members on the... Read more at https://www.sirajlive.com/walayar-mob-lynching-case-accused-granted-bail-by-mannarkkad-sc-st-special-court-after-90-days-remand.html</p>	04:02 Min	Breaking News	abc	
17.05.2026	Pratidin TV	19:41	<p>Balianta lynching case Mock Drill</p> <p>-Balianta incident: Police in action mode, mock drill underway at the scene! After the Balianta incident, the police preparedness, on the instructions of the DCP of Cuttack, showed how quickly the ACP of Zone-5 and the police station officers under him were able to reach the scene and arrest the criminal. They conducted a mock drill and showed the dummy.</p>	03:09 Min	Breaking News	Abc	

17.05.2026	News18 Gujarati	10:10	Surendranagar Caste Discrimination -A scheduled caste family has been ostracized and accused of abduction in Metasar village of Patdi taluka of Surendranagar... A video has gone viral alleging that the family was not allowed to fill water from a well. The locals have requested the District Collector's office to take action against those responsible in this matter. After registering a complaint, the police have registered a case against 6 accused under sections including the Atrocities Act and are investigating... The viral video has also been subjected to FSL investigation.	02:39 Min	Breaking News	Abc	
17.05.2026	IBC24	10:20	Mandsaur : 2 साल पुराने सिजेरियन ऑपरेशन मामले में कार्रवाई। 4 वरिष्ठ डॉक्टरों पर हुई कार्रवाई	06:15 Min	Breaking News	abc	
17.05.2026	News18 India	16:00	जोधपुर की दो बहनों की मृत्यु आत्महत्या नहीं, BJP सरकार और ध्वस्त कानून व्यवस्था द्वारा किया गया "संस्थागत मर्डर" है। बेटियां ब्लैकमेल, गैंगरेप और दरिंदगी झेलती रही, और सड़ा हुआ सिस्टम एवं पुलिस चुपचाप सब कुछ देखती रही। FIR के बाद भी अपराधी खुलेआम घूमते रहे और कहते रहे कि "पुलिस हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती"। आखिर दरिंदों को ये हौसला कौन दे रहा था?	02:18 Min	Breaking News	Abc	

